अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	पचपदरा रिफाइनरी : पश्चिमी राजस्थान के विकास की वाहक
2.	'जयपुर मेट्रो फेज - 2 परियोजना' का शिलान्यास
3.	प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा (04 जुलाई, 2026)
4.	IIT जोधपुर बना 'CMS कोलाबरेशन' का पूर्णकालिक सदस्य
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. 'प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन' में जयपुर देश भर में प्रथम स्थान पर 2. डॉ. सुनील सिंह : CM एक्सीलेंस अवॉर्ड – 2026 3. 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप - 2026 में राजस्थान
6.	समुद्री विकास कोष (एमडीएफ)
7.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 9 वर्ष
8.	मानस पहल (मादक पदार्थ निषिद्ध असूचना केंद्र)
9.	चिकित्सा नवाचार पेटेंट मित्रा पहल
10.	सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी: भारत
11.	अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगाँठ पर भारत-अमेरिका संबंध
12.	रक्षा अधिग्रहण परिषद

राजस्थान परिदृश्य

पचपदरा रिफाइनरी : पश्चिमी राजस्थान के विकास की वाहक

चर्चा में क्यों?

- 04 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पचपदरा (बालोतरा) में 'देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स' का लोकार्पण किया।

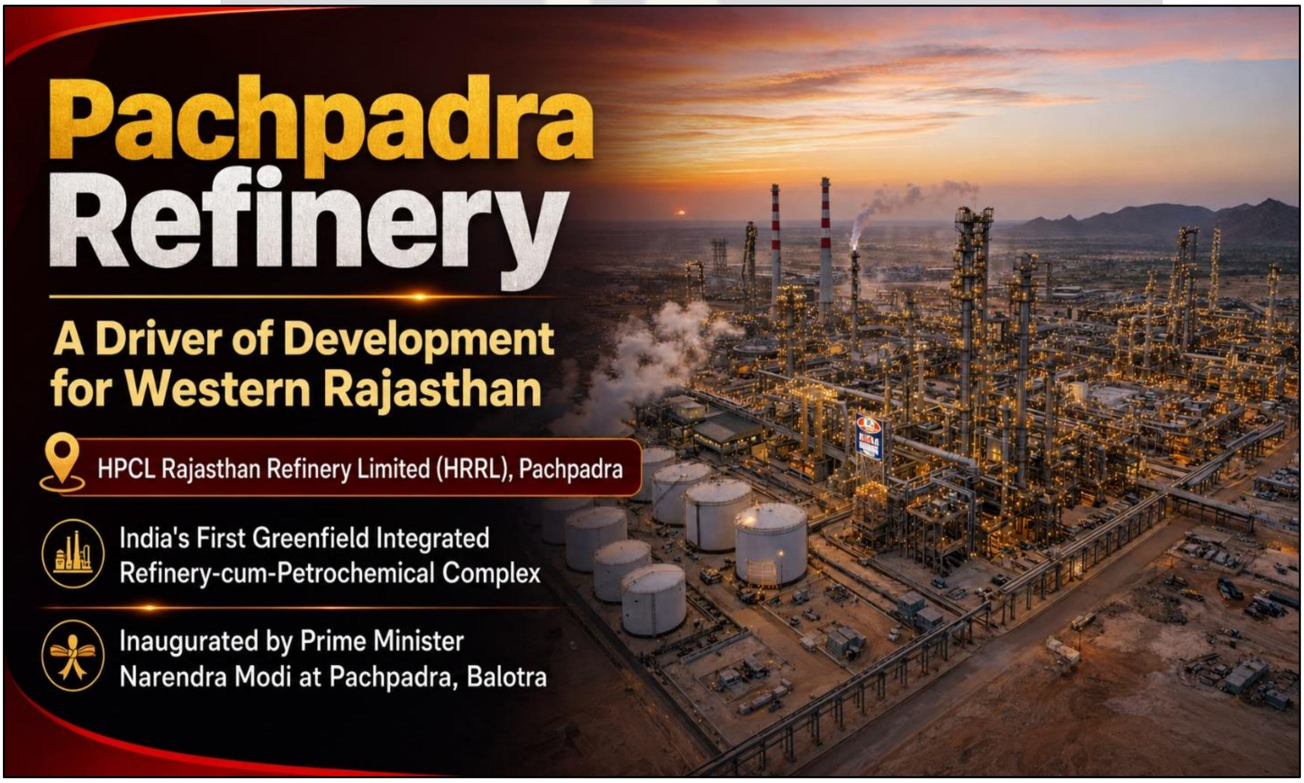

मुख्य बिन्दु:

- पचपदरा स्थित यह राजस्थान की पहली और देश की 24वीं रिफाइनरी है।
- **नाम :** HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL), पचपदरा।
- **कुल निवेश :** ₹79,459 करोड़।
- **संचालन :** परियोजना का कार्यान्वय HRRL द्वारा किया जा रहा है, जो HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **परियोजना को स्वीकृति :** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर, 2017 को।
- **इक्विटी भागीदारी :** हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत।
- **BS-6 मानक वाली देश की प्रथम परियोजना :** यह BS-6 मानक वाली देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 (बेहद उच्चस्तरीय) है तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और संधारणीयता के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- **उत्पादन क्षमता :** 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है, जिसमें 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं।
- इस रिफाइनरी में आयातित कच्चे तेल (7.5 MMTPA) के साथ-साथ राजस्थान में उत्पादित क्रूड ऑयल (1.5 MMTPA) को भी संसाधित (Processed) किया जा सकेगा।

महत्त्व :

- पचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रो कॉम्प्लेक्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- साथ ही, यह पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधारभूत उद्योग के रूप में कार्य करेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं अनुषंगी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस रिफाइनरी की देश के कुल कच्चे तेल प्रोसेसिंग में 3.5 फीसदी की हिस्सेदारी होगी जबकि यह प्रोसेसिंग क्षमता के लिहाज से देश की 13वीं बड़ी रिफाइनरी होगी।
- रिफाइनरी से राजस्थान ना केवल कच्चा तेल निकालने वाला राज्य रहेगा बल्कि वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट (पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिमर) उत्पादित करने का हब बनेगा। इससे राज्य में प्लास्टिक और केमिकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **रिफाइनरी से उत्पादित होने वाले प्रमुख उत्पाद :** प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) पेट्रोल और 4 MMT डीजल के उत्पादन के साथ-साथ, यह प्रति वर्ष 1 MMT पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 MMT लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (LLDPE), 0.5 MMT हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन (HDPE) और लगभग 0.4 MMT बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडीन का उत्पादन।
- ये सभी उत्पाद परिवहन, फार्मा, पेंट, पैकेजिंग उद्योग आदि क्षेत्रों में ऊर्जा और औद्योगिक इको-सिस्टम के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ)

- **विकास :** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) द्वारा।
- **स्थान :** पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के पास।
- **उद्देश्य :** यह पेट्रो जोन रिफाइनरी से निकलने वाले सह-उत्पादों (Downstream Products) का उपयोग करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जा रहा है।
- पचपदरा रिफाइनरी से 12 किमी दूर स्थित राजस्थान पेट्रो जोन अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से जुड़ा हुआ है।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

1. पचपदरा रिफाइनरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(i) यह राजस्थान की पहली और देश की 24वीं रिफाइनरी है।

(ii) इसका संचालन HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम HRRL द्वारा किया जा रहा है।

(iii) इसमें HPCL और राजस्थान सरकार की इक्विटी भागीदारी क्रमशः 26% और 74% है।

सत्य कथनों का चयन कीजिए-

(a) केवल (i) और (ii) (b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (i) और (iii) (d) उपर्युक्त सभी

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

‘जयपुर मेट्रो फेज - 2 परियोजना’ का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

- 4 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पचपदरा से वर्चुअली ‘जयपुर मेट्रो फेज - 2 परियोजना’ का शिलान्यास किया।

मुख्य बिन्दु:

- **परियोजना की कुल लागत :** ₹13,037.66 करोड़ रुपये। (PIB के अनुसार)
- **विस्तार :** प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़ तक कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे। (34 एलिवेटेड तथा 2 भूमिगत स्टेशन शामिल।)
- **कुल लंबाई :** 41 किलोमीटर द्वारा उत्तर-दक्षिण मेट्रो गलियारा निर्मित किया जाएगा।
- **हिस्सेदारी :** भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50:50 प्रतिशत।
- **निर्माण एवं संचालन :** जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित राज्य की भावी मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण एवं संचालन भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम ‘राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (RMRCL)’ द्वारा किया जाएगा।

- **कार्यावधि : सितंबर, 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य।**
- **यह परियोजना राजस्थान सार्वजनिक परिवहन-केंद्रित विकास नीति-2025, प्रस्तावित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण सुधार और राष्ट्रीय सतत शहरी परिवहन उद्देश्यों के अनुरूप है।**

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का चरणबद्ध विस्तार (राजस्थान आर्थिक समीक्षा – 2025-26)

चरण	विवरण	लागत	वित्त पोषण
चरण–1A (मानसरोवर से चाँदपोल तक)	संचालन - 3 जून, 2015 से।	₹2023 करोड़।	पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
चरण–1B (चाँदपोल से बड़ी चौपड़)	संचालन - 23 सितम्बर, 2020 से। लंबाई - 2.01 किलोमीटर। नोट : निर्माण के दौरान शहर की विरासत को संरक्षित रखते हुए कार्य किया गया।	₹1126 करोड़	एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹810 करोड़ का ऋण, शेष राजस्थान सरकार द्वारा।
चरण–1C (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा DPR तैयार कर दी गई है।	₹1511.07 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

चरण–1D (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा DPR तैयार कर दी गई है। परियोजना कार्यान्वयन हेतु कार्य प्रगति पर है।	₹222.15 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण–2 (प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़)	जयपुर मेट्रो ने यातायात एवं परिवहन परामर्शदाता के रूप में मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया है। फेज–2 (प्रहलादपुरा /सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र/हल्दीघाटी मार्ग/हवाई अड्डा/अंबाबाड़ी/विद्याधर नगर/टोंक रोड) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है।	₹13532.92 करोड़	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

1. जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

(a) इस परियोजना में कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे।

(b) इसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे।

(c) इसकी कुल लंबाई 41 किलोमीटर होगी।

(d) इसे पूर्णत: राजस्थान सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

2. जयपुर मेट्रो फेज-2 का निर्माण एवं संचालन किसके द्वारा किया जाएगा?

(a) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

(b) राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

(c) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

(d) जयपुर विकास प्राधिकरण

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा (04 जुलाई, 2026)

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई, 2026 को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे के दौरान ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

मुख्य बिन्दु:

1. **जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन :** प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट पर ₹480 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
   - एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी प्रति वर्ष यात्री क्षमता 20 लाख है। राजस्थान की समृद्ध विरासत से प्रेरित वास्तुकला से निर्मित यह टर्मिनल भवन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है।
   - **संशोधित उड़ान (UDAN) योजना :** प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) को मजबूत करने के लिए जोधपुर से संशोधित उड़ान (UDAN - उड़े देश का आम नागरिक) योजना का शुभारंभ किया।
   - इस महत्त्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करना और किफायती हवाई यात्रा सुलभ बनाना है।
   - इस योजना के तहत एयरलाइन कंपनियों के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक की वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता का प्रावधान है। इससे क्षेत्रीय परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी।

2. HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण।
3. जयपुर मेट्रो फेज – 2 का शिलान्यास।
4. पावरग्रिड बाड़मेर-प्रथम ट्रांसमिशन लिमिटेड परियोजना की आधारशिला।
5. पावरग्रिड ब्यावर-दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड परियोजना का उद्घाटन।
6. 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन।
7. 300 मेगावाट करणीसर सोलर पावर प्लांट बीकानेर परियोजना का उद्घाटन।
8. 4-लेन जोधपुर रिंग रोड सेक्शन-।। परियोजना का उद्घाटन।
9. चूरू-सादुलपुर रेल मार्ग तथा चूरू-रतनगढ़ रेल मार्ग का उद्घाटन।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **पट्टू (Pattu) :** मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को पश्चिमी राजस्थान की पारंपरिक हस्तकला से निर्मित 'पट्टू' (एक विशेष प्रकार का पारंपरिक बुना हुआ कंबल) भेंट किया।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कितनी परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई, 2026 के राजस्थान दौरे से संबंधित हैं?

(i) HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण

(ii) जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास

(iii) 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन

(iv) चूरू-सादुलपुर और चूरू-रतनगढ़ रेल मार्ग का उद्घाटन

सही विकल्प का चयन कीजिए-

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

IIT जोधपुर बना 'CMS कोलाबरेशन' का पूर्णकालिक सदस्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर CERN, जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) की प्रतिष्ठित CMS (कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड) कोलाबरेशन का पूर्ण सदस्य बना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

मुख्य बिन्दु:

- **IIT जोधपुर का CMS में शामिल होना भारत की वैश्विक विज्ञान एवं अनुसंधान में बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है।**
- **नेतृत्व : IIT जोधपुर के CMS कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. लता पंवार और डॉ. जितेंद्र कुमार करेंगे।**
- **CMS (कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड) : CMS (कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड) CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) का एक प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोग है। वर्ष 2012 में इसी प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन (Higgs boson) की ऐतिहासिक खोज की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से 'God Particle' भी कहा जाता है। इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है।**
- **CERN, जिनेवा : CERN (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन) विश्व की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला (Particle Physics Laboratory) है, जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) स्थापित है।**
- **यह दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सलरेटर है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पदार्थ की मूल संरचना तथा प्रकृति के मौलिक नियमों को समझने का प्रयास करते हैं।**
- **इस प्रतिष्ठित सदस्यता के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों और अग्रणी शोध संस्थानों के उस अंतरराष्ट्रीय समूह का हिस्सा बन गया है, जो मानवता के सबसे महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।**
- **पूर्ण सदस्य बनने के बाद IIT जोधपुर के वैज्ञानिक CMS कोलाबरेशन के दीर्घकालिक वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।**

- साथ ही, संस्थान के शोधकर्ता पार्टिकल फिजिक्स के अत्याधुनिक अनुसंधान, नई पीढ़ी की डिटेक्टर तकनीकी के विकास तथा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में होने वाली पार्टिकल कोलाइजन से प्राप्त विशाल डेटा के विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेंगे।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

Q. हाल ही में, कौनसा संस्थान जिनेवा की CMS कोलाबरेशन का पूर्ण सदस्य बना?

(a) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर।

(b) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर।

(c) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा।

(d) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**'प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन' में जयपुर देश भर में प्रथम स्थान पर** ■ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की हालिया रिपोर्ट 'लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन-प्लस सिटीज' के अनुसार, जयपुर प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर है। ■ हालाँकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता यानी सकल मूल्य वर्धन (GVA) के मामले में जयपुर देश में 12वें स्थान पर है। ■ NSO द्वारा जारी यह रिपोर्ट 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 46 शहरों में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन का आकलन करती है।
2.	**डॉ. सुनील सिंह : CM एक्सीलेंस अवॉर्ड - 2026** ■ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉ. सुनील सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग सॉल्यूशन विकसित किया है। ■ इस उत्कृष्ट नवाचार के लिए उन्हें CM एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया। ■ वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले डॉक्टर हैं। यह AI आधारित तकनीक मधुमेह मरीजों में आँखों की गंभीर बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी (DR) की शुरुआती पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने और दृष्टि हानि के खतरे को कम करने में मदद करेगी।

3.	**21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप - 2026 में राजस्थान** ■ **आयोजन :** देहरादून के हिमाद्रि आइस रिंक में 25 से 30 जून, 2026 तक। ■ इस प्रतियोगिता में 'आइस स्केटिंग फाउंडेशन ऑफ राजस्थान' के 46 स्केटर्स के दल ने हिस्सा लिया था। ■ **ट्विशा शारदा (जयपुर) :** जयपुर की फिगर स्केटर ने रजत पदक जीता। ■ **मायरा त्यागी (उदयपुर) :** एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। ■ इसके अलावा, राजस्थान के आरित्रा कुमार, जयश्री खंडेलवाल, विधि भट्ट और सैशा का चयन एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के लिए किया गया।

UTKARSH CIVIL SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

समुद्री विकास कोष (एमडीएफ)

चर्चा में क्यों?

- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने समुद्री विकास कोष (MDF) के तहत स्थापित किए जा रहे समुद्री निवेश कोष (MIF) पर एक उद्योग परामर्श का आयोजन किया।

मुख्य बिन्दु:

एमडीएफ

- समुद्री क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सितंबर, 2025 में स्थापित किया गया।

दो घटक:

- **समुद्री निवेश कोष (MIF):** भारत सरकार का योगदान 49% है, शेष राशि अन्य संस्थागत, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निवेशकों से जुटाई गई है।
- **ब्याज प्रोत्साहन कोष (आईआईएफ):** पूरी तरह से भारत सरकार के बजटीय समर्थन से वित्त पोषित।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 9 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से नौ वर्ष पूरे कर लिये हैं।

मुख्य बिन्दु:

- हालिया अगली पीढ़ी के GST संबंधी सुधारों ने कर संरचना को और सरल बनाया है, दरों में कमी की है, अनुपालन को सरल बनाया है और घरों, MSME, व्यवसायों तथा भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने में GST की भूमिका को सुदृढ़ किया है।

9 वर्षों में GST की उपलब्धियाँ

- **राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण:** GST ने भारत की खंडित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को "एक देश, एक कर" के सिद्धांत पर आधारित एक एकीकृत ढाँचे से बदल दिया। इसने 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को समाहित किया, जिससे कर विखंडन, अदृश्य लागत एवं कैस्केडिंग प्रभाव कम हुए।
- **करदाता आधार का विस्तार:** GST करदाताओं की संख्या वर्ष 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 1.65 करोड़ हो गई, जो अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिकीकरण और व्यापक कर संबंधी अनुपालन को दर्शाता है।
- **मज़बूत राजस्व वृद्धि:** विगत पाँच वर्षों में, संग्रह वर्ष 2021-22 में लगभग 13.76 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 22.27 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- **आर्थिक गतिविधि का उच्च-आवृत्ति संकेतक:** GST संग्रह उपभोग, व्यापार, अनुपालन और आर्थिक औपचारिकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक बन गया है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **सहकारी संघवाद का सुदृढ़ीकरण:** जीएसटी परिषद ने कर संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्यों को एक साथ लाने का कार्य किया है।
- **कर प्रशासन का डिजिटल परिवर्तन:** गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने करदाताओं, केंद्र, राज्यों और अन्य हितधारकों के लिये एक सामान्य डिजिटल अवसंरचना प्रदान की है। ई-इनवॉइसिंग, पूर्व-भरे रिटर्न, वास्तविक-समय सत्यापन तथा डिजिटल समाधानों ने पारदर्शिता में सुधार किया है और मैनुअल रिपोर्टिंग त्रुटियों को कम किया है।
- **छोटे करदाताओं के लिये अनुपालन में आसानी:** GST सुधारों ने उच्च छूट सीमा, कंपोज़ीशन स्कीम, त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना, SMS के माध्यम से शून्य रिटर्न दाखिल करना और कम जोखिम वाले आवेदकों के लिये त्वरित पंजीकरण के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाया है।

RAS MODEL QUESTION:

Q. "जीएसटी परिषद भारत में सहकारी संघवाद के एक अनूठे प्रतीक के रूप में उभरी है, फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय स्वायत्तता को लेकर संतुलन बनाना एक सतत चुनौती है।" समीक्षा कीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

मानस पहल (मादक पदार्थ निषिद्ध असूचना केंद्र)

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (MANAS) नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत कर रही है, जिसके तहत नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- MANAS को गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वावधान में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के सहयोग से 2024 में लॉन्च किया गया था ।
- यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933, आधिकारिक पोर्टल, ईमेल और UMANG ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
- मानस डिजिटल इंडिया की परिकल्पना और नशा मुक्त भारत के मिशन को एक साथ लाता है।

MCQ:

Q. हाल ही में चर्चा में रही 'मानस' (MANAS) पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

(B) नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना और पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच बनाना।

(C) सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की निगरानी करना।

(D) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

चिकित्सा नवाचार पेटेंट मित्रा पहल

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सभी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी है।

मुख्य बिन्दु:

चिकित्सा नवाचार पेटेंट मित्रा पहल

- मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र पहल एक केंद्रीकृत, विशेषज्ञ-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक संस्थागत बौद्धिक संपदा (आईपी) इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है।
- यह शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों द्वारा विकसित जैव चिकित्सा संबंधी अभूतपूर्व उपलब्धियों की सुरक्षा, प्रबंधन, रखरखाव और व्यावसायीकरण के लिए संपूर्ण और व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है।
- **प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अंतर्गत विकसित और प्रबंधित।

MCQ:

Q. 'चिकित्सा नवाचार पेटेंट मित्रा' प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) देश के सभी मेडिकल छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना।

(B) चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

(C) चिकित्सा शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के जैव चिकित्सा नवाचारों की सुरक्षा, प्रबंधन और व्यावसायीकरण में सहायता करना।

(D) निजी अस्पतालों के लिए नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी: भारत

चर्चा में क्यों?

- **भारत ने दोहराया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता।**

मुख्य बिन्दु:

- **भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था।**

सिंधु जल संधि

- **हस्ताक्षर:** 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच, विश्व बैंक के मध्यस्थ/सुविधाकर्ता के रूप में।
- **शामिल नदियाँ:**
  - **पूर्वी नदियाँ (रावी, व्यास और सतलुज):** भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित।
  - **पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चिनाब):** पाकिस्तान को आवंटित।
- संधि के अनुसार, भारत को घरेलू उद्देश्यों, गैर-उपभोक्ता उपयोगों, सिंचाई और नदी-आधारित जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सीमित उपयोग की अनुमति है।
- **IWT के तहत विवाद समाधान:**
  - **चरण 1:** प्रत्येक देश से एक आयुक्त के साथ स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी)। (दोनों देशों में बारी-बारी से वार्षिक बैठक होती है)।
  - **चरण 2:** तटस्थ विशेषज्ञ (विश्व बैंक द्वारा नियुक्त) और इसमें बाध्यकारी निर्णय देना शामिल है।
  - **चरण 3:** पक्षों के बीच समझौते पर या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थता न्यायालय।

सिंधु जल संधि के निलंबन के निहितार्थ

पाकिस्तान के लिए:

- **खाद्य असुरक्षा:** सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की 80% से अधिक खाद्य फसलों की सिंचाई करती है।
- **अर्थव्यवस्था:** सिंधु प्रणाली पर निर्भर गेहूँ, चावल और कपास ने निर्यात से 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022) अर्जित किए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **बिजली और पानी का संकट:** पाकिस्तान की लगभग एक तिहाई बिजली जलविद्युत स्रोतों से आती है, जबकि देश पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहा है।

भारत के लिए:

- **जल संसाधनों का शस्त्रीकरण:** पाकिस्तान के राज्य-आतंक गठजोड़ पर वैश्विक ध्यान ।
- हालांकि, इससे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित ऊपरी देशों, विशेष रूप से चीन के लिए इसी तरह की रणनीतियों को अपनाने का एक उदाहरण स्थापित हो सकता है।
- **एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में विश्वसनीयता:** एकतरफा निलंबन को संधि प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है।
- **पारिस्थितिक असंतुलन:** नई जल अवसंरचना परियोजनाएँ जैव विविधता से समृद्ध और भूकंपीय रूप से संवेदनशील सिंधु बेसिन को प्रभावित कर सकती हैं।

RAS MODEL QUESTION:

Q. सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत द्वारा नए जल बुनियादी ढाँचे के विकास से उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक असंतुलन और भू-गर्भीय जोखिमों की चर्चा कीजिए। क्या 'जल का शस्त्रीकरण' राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक स्थायी विकल्प है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगाँठ पर भारत-अमेरिका संबंध

चर्चा में क्यों?

- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच संबंध शीत युद्ध के दौरान की दूरी से नाटकीय रूप से बदलकर एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए हैं।

मुख्य बिन्दु:

भारत-अमेरिका संबंधों का ऐतिहासिक विकास

- **शीत युद्ध का दौर और अलगाव (1947-1990):**
  - **गुटनिरपेक्षता की नीति :** स्वतंत्रता के बाद, भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई , जिससे वाशिंगटन से भू-राजनीतिक दूरी बनी रही।
- **घर्षण के बिंदु :**
  - **1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध:** भारत ने भारत-सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में बंगाल की खाड़ी में यूएसएस एंटरप्राइज टास्क फोर्स तैनात की।
  - **परमाणु तनाव:** भारत के 1974 के "स्माइलिंग बुद्धा " परीक्षण ने अमेरिका के निर्यात नियंत्रण को जन्म दिया। 1998 के पोखरण-II परीक्षणों के परिणामस्वरूप तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए।
- **निर्णायक मोड़ (1991-2024):**
  - **आर्थिक उदारीकरण (1991):** शीत युद्ध की समाप्ति और भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों ने बाजारों को खोल दिया और संबंधों में नरमी की शुरुआत की।
  - **कूटनीतिक बदलाव (1999-2001):** 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान, अमेरिका ने पाकिस्तान पर सेना वापस बुलाने के लिए दबाव डाला। 2001 तक, शेष परमाणु प्रतिबंध हटा दिए गए थे।
  - **महत्त्वपूर्ण उपलब्धि (2008):** भारत -अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते ने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया और दोनों लोकतंत्रों के बीच मूलभूत विश्वास का निर्माण किया।

- o **भारत रक्षा भागीदार के रूप में (2016):** LEMOA (लॉजिस्टिक्स), COMCASA (संचार), BECA (भू-स्थानिक), आदि जैसे मूलभूत रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- o **इंडो-पैसिफिक फोकस (2017):** चीन को लेकर आपसी चिंताओं के कारण जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) का पुनरुद्धार हुआ।

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति (2025-26)

आर्थिक और व्यापारिक गतिशीलता :

- अमेरिका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार (वस्तुओं + सेवाओं) 200 अरब डॉलर से अधिक है (भारत को व्यापार अधिशेष है) और 500 अरब डॉलर तक पहुँचने की महत्वाकांक्षा है।
- **2025 में टैरिफ संबंधी तनाव:** भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ (50% तक) लागू किए।
- **2026 अंतरिम व्यापार ढाँचा:** कई भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर लगभग 18% कर दिया गया है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**
  - o **अधिग्रहीत/एकीकृत प्रमुख प्लेटफॉर्म:** सी-17 ग्लोबमास्टर, सी-130जे, पी-8आई पोसाइडन, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, एमएच-60आर सीहॉक।
  - o **2025 का 10-वर्षीय ढाँचा:** प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किए गए, जो अंतरसंचालनीयता (भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष, साइबर), सह-विकास और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित है।
  - o **संयुक्त अभ्यास:** युद्ध अभ्यास (सेना), वज्र प्रहार, मालाबार (क्वाड भागीदारों के साथ नौसेना) जैसे नियमित अभ्यास।

RAS MODEL QUESTION:

Q. "रणनीतिक और रक्षा सहयोग में प्रगाढ़ता के बावजूद, व्यापारिक मोर्चे पर टैरिफ संबंधी तनाव भारत-अमेरिका संबंधों की एक सतत् आंतरिक चुनौती बने हुए हैं।" वर्ष 2025-26 के हालिया टैरिफ विवादों और रूसी तेल खरीद के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विज्ञान प्रौद्योगिकी

रक्षा अधिग्रहण परिषद

चर्चा में क्यों?

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने कई हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए पूँजीगत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

- **रक्षा अधिग्रहण परिषद:** (अध्यक्ष: रक्षा मंत्री) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना में पूँजीगत अधिग्रहणों को 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी देता है और अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रमुख हथियार प्रणाली को मंजूरी

- **आकाश तरंग:** भारतीय सेना के लिए मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली।
- हार्ड किल के विपरीत, यह केवल आवृत्ति को बाधित करता है, जीपीएस/जीएनएसएस को जाम करता है और ड्रोन और ऑपरेटर के बीच संचार को काट देता है (सॉफ्ट किल) ।
- **मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MR-SAM):** इसे इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 70 किमी से अधिक है और यह बराक-8 मिसाइल पर आधारित है।
- **बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली (वी-शोराड्स):** कम दूरी पर निम्न ऊँचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए ।
- यह स्वदेशी रूप से विकसित मानव-चालित वायु रक्षा प्रणाली है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213